(f) Government of Andhra Pradesh has restored the earlier position which provided for priority in procurement for Government supplies to the handloom sector and handloom agencies.

(g) Government of Andhra Pradesh has arranged distribution of ex-gratia of Rs. 5,000 per family of deceased weaver through non-governmental agencies. 72 families have been provided such assistance.

(h) 2455 weavers have been sanctioned loans @ Rs. 1,000/- by commercial banks.

(i) Weakness of primary societies has been one of the problems. Apart from the scheme meant for destitute weavers referred to above, Government of Andhra Pradesh has taken steps to hold fresh elections for weavers cooperative societies all over the State so as to revitalise them.

(c) Indian textile and clothing exports are the single biggest commodity exported from the country, accounting for about 25 per cent of Indian exports. The total handloom exports constitute 10 per cent of the overall textile and clothing exports in the country. Considering the need to earn foreign exchange, it may not be possible to retain mill cloth for domestic market. Government have however been taking a number of steps to boost exports of handloom products. Under the new quota policy, 3 per cent of textiles quota and 2 per cent of garments quota has been reserved for handlooms.

रेशम डिजाइन-सह-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

*178. **डा० बापू कालवाते**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ने रेशम डिजाइन-सह-अनुसंधान केन्द्र बनाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ऐसा एक केन्द्र और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 24 जनवरी 1992 को हुए परिषद के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद अध्यक्ष ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि सरकार राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत रेशम डिजाइन-सह-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिये निधियों का आवंटन कर सकती है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने लगभग 1 करोड़ रु० के व्यय पर राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत एवं डिजाइन केन्द्र की स्थापना करने के लिये पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है । बोर्ड के बंगलौर में स्थित केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान में स्थापित किये जा रहे केन्द्र में निम्नलिखित उप-एकक होंगे :—

(1) डिजाइन कलेक्शर तथा डुप्लीकेशन (म्यूजियम)

(2) आर्ट स्टेडियो

(3) प्रशासन अनुसंधान अध्ययन

(4) कम्प्यूटर की सहायता से वस्त्र डिजाइन (डी ए टी ई) तथा कलर मैचिंग

(5) वूवन तथा प्रिंटिंग डिजाइन का एनीवेशन ।